

राष्ट्रीय-10

गो तस्करों को देखते ही गोली मारने
का आदेश दूंगा: कर्नाटक के मंत्री

चुनाव से पहले मोदी ने राहुल, केरीबाल पर बोला हमला



प्रधानमंत्री नईदे मोदी ने नई दिल्ली में संसद के बाट सत्र के दैशन लोकसभा में दाप्रति के अनिवार्य पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विषय के नेता राहुल गांधी पर तीक्ष्ण हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग खुलासा को प्रयागराज में महाकुंभ मेला का दोरा करेंगे और वे भासा बोल रहे हैं और कहा कि जो लोग भासा राज्य के खिलाफ 'युद्ध की घोषणा' करते हैं, वे न तो संविधान को समझ सकते हैं और न ही संविधान के बारे में। देश की एकता उड़ाने दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक बाट पहले अर्थव्यवस्था के बारे में और पर एक कटाई करते हुए कहा, 'कुछ पार्टीय युद्धों के भवित्व के लिए आप-दा' की तरह है।' मोदी ने बात किया कि उनकी सरकार को योजनाओं से काफी धन की बचत हुई, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल 'शीश महल' बनाने में नहीं किया।

लोकसभा में शारपति के अधिभासण पर धन्यवाद देते हुए उड़ाने राहुल पर कई परोक्ष हमले किए और कहा कि जो लोग गांधीय युद्धों के भवित्व के लिए आप-दा की तरह हैं। मोदी ने कहा कि भारत की आधारात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आधारात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। पीएमओ ने कहा कि भारत की आधारात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर खुलासा करते हुए कहा, 'इससे पहले, 13 दिसंबर, 2024 को प्रयागराज की अनीय योजना के दैशन, प्रधानमंत्री ने आप जनता के लिए संपर्क, संविधानों में सुधार के लिए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।'

प्रधानमंत्री आज पवित्र संगम में लगाएंगे दुबकी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेला का दोरा करेंगे और कहा कि कुछ लोग खुलासा को बढ़ावा देंगे तो पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को एक बाट बनाने में यह जनवारी दी। महाकुंभ 2025, पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवारी को शुरू हुआ और वह 26 फ़रवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। पीएमओ ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आधारात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। पीएमओ ने कहा कि भारत की आधारात्मिक और सांस्कृतिक विधानसभा चुनाव से एक बाट पहले अर्थव्यवस्था के बारे में और पर एक कटाई करते हुए कहा, 'कुछ पार्टीय युद्धों के भवित्व के लिए आप-दा' की तरह है।' मोदी ने बात किया कि उनकी सरकार को योजनाओं से काफी धन की बचत हुई, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल 'शीश महल' बनाने में नहीं किया।

मोदी ने गांधी परिवार का नाम लिए और विधानसभा चुनावों से एक बाट चल रहे परिवारों के भवित्व के लिए आप-दा की तरह हैं। मोदी ने कहा कि भारत की आधारात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के बाट बढ़ावा देने और संरक्षित करने के अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर खुलासा करते हुए कहा, 'इससे पहले, 13 दिसंबर, 2024 को प्रयागराज की अनीय योजना के दैशन, प्रधानमंत्री ने आप जनता के लिए संपर्क, संविधानों में सुधार के लिए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।'

महिलाओं को किस तरह से कठिनाई में रहने के लिए मजबूर किया। हमने उड़े अधिकार देने के लिए तीन तलक बढ़ावा देने को कठिन बढ़ावा देने की योजनाओं की भासा बोल रहे हैं। शहरी नवसलियों की भासा बोलने वाले, भासी योजनाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाले ये लोग न तो संविधान को समझ सकते हैं और न ही संविधान के बारे में। मोदी ने कहा, "यह देश की एकता के लिए है।"

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज कुछ लोग खुलासा करते हुए यह आधारात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रियपात्री प्रियों द्वारा दुर्लभ लिया गया है कि वे लोग गरीबों के लिए आज अब भासा, आरएसएस और ईंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं।

यद्यपि मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, ल

ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਏਮਏਲਾਏ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕੀ
1,000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਸੱਥਿਤ ਜਲਦ ਕੀ

नई दिल्ली (भागा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने हाल में चेन्नई से संचालित एक कंपनी के खिलाफ तलाशी के बाद 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस कंपनी पर छत्तीसगढ़ में धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपी कंपनी-आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) और संबंधित व्यक्तियों अंडाल अस्मुमाम, एस अस्मुमाम तथा अन्य के परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई। महत्वपूर्ण हिस्सा अधिक मूल्य पर संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए आरकेएमपीपीएल द्वारा नियंत्रित एमआईपीपी नामक एक विदेशी इकाई को स्थानांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन के बाद आरकेएमपीपीएल ने 240 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर अपने 26 प्रतिशत शेयर मलेशिया आधारित मुदज्या कॉर्पोरेशन बीएचडी को और 10.95 प्रतिशत शेयर एनके इंटरनेशनल होलिडंग्स लिमिटेड को सौंप दिए। ईडी के अनुसार, इसके विपरीत, आरकेएमपीपीएल को अंकित मूल्य पर 63.05 प्रतिशत शेयर आवंटित किए गए थे।

इसने कहा कि धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से संबंधित है, जिसमें आरोपियों पर छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक धोखाखाड़ी से प्राप्त करने का आरोप है। संबंधित कोयला ब्लॉक बिजली क्षेत्र के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित किया गया था। टिप्पणी के लिए कंपनी या इसके प्रवर्तकों से संपर्क नहीं किया जा सका। आरोप है कि आरकेएमपीपीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण प्राप्त किया था और इस कोष का 3,800 करोड़ रुपए का एक

मूल्यांकन पद्धति में पारदर्शिता की कमी थी और निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं रखा गया। एंजिसी ने कहा कि यह पायथंग गया कि मुदजया कॉरपोरेशन ने अपनी सहायक कंपनी एमआईआईपीएल इंटरनेशनल से उपकरण खरीद के लिए पीएफसी-स्वीकृत धनराशि की, फिर से वापसी के जरिए अपने 2400 रुपए प्रति शेयर प्रीमियम के पोषण किया। इसने दावा किया कि अनुमानित तौर पर इक्ट्रिटी भागीदारी की आड़ में विदेशी संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से 1,800 करोड़ रुपए आरकेएमपीपीएल के वापस भेज दिए गए।

**संभल में प्राचीन चतुर्मुख कूप का
जीर्णोद्धार किया जाएगा**

संभल (भाषा) । संभल जिला प्रशासन ने प्राचीन चतुर्मुख कूप का जीणोद्धार मॉडल कूप के रूप में करने और जिले के अन्य धार्मिक तीर्थ स्थलों के उत्थान की योजना बनाई है । अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव शीघ्र ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा । नगर पालिका के अधिकारियों ने अधिकारियों सभी धूषण तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि जिलाधिकारी ने क्षेत्र के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया । उन्होंने कहा, नगर क्षेत्र में 19 प्राचीन कूप हैं और उनका जीणोद्धार किया जा रहा है । इन जगहों पर बेहतर पहुंच मार्ग, प्रवेश द्वार बनाने तथा सूचना पट्टी लगाने की योजना है । उन्होंने बताया कि भद्रक आश्रम, पाप मोचन तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ तथा शंख माधव तीर्थ को विकसित करने के लिए वंदन योजना के तहत प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार को भेजा जाएगा । चतुर्मुख कूप के बारे में उन्होंने कहा, इसे एक मॉडल कूप के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके तहत इसकी प्राचीन संरचना को बनाए रखते हुए उसी ऐतिहासिक ईंटों का उपयोग किया जाएगा आकर्षण को बढ़ाने के लिए इस स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय कराई जाएंगी । उन्होंने बताया कि सभी तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वारों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनके ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की झलक दिखे । उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्थल से संबंधित इतिहास और तथ्यों के भगवान कल्पि के अवतारों के चित्रण के साथ प्रदर्शित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को क्षेत्र की विरासत के बारे में बताया जा सके ।

**अत्परसंख्यकों के लिए स्वर्ग है भारत, मोदी
को मसीहा मानते हैं सिखः लालपुरा**

नई दिल्ली(भाषा)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मंगलवार को कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ण है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सिख पिछले 10 वर्षों में समुदाय के लिए किए गए कार्यों के लिए मसीहा मानते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालपुरा ने यहां पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में अल्पसंख्यकों से जुड़े महों पर बात की। उन्होंने कहा, भारत

लालपुरा ने कहा, भारत ने सभी अवसर दिए हैं, अब केंद्रीय सेवाओं में 62 अधिकारी मुस्लिम समुदाय हैं, 11 जैन समुदाय से हैं। जो १० सक्षम है वह जहां चाहे वहां पहुँच सकता है। लालपुरा ने यह दावा किया कि सिख प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने समुदाय के लिए पिछले 10 वर्षों में जो किया है, वह पहले किसी ने करने के बारे सोचा भी नहीं था।

एनसीएम अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने करतारायर गलियारा खुलवाया... वर्तमान बाल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने सिखों के इतिहास का ध्यान रखा और लाल किटे से गुरु तेग बहादुर व चौथी जन्मशती मनाई है, जहां उनकी हत्या का आदेश दिया गया था। वर्तमान सरकार सिख समुदाय के सभी मुद्दों को हल करने पर काम ब

एक-दो साल में उहिन कांत आय पर कर छूट चाहिए लाख रुपए लोग नई व्यवस्था में बदल ही एक- व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पांडेय ने डिफॉल्ट है। यानी अगर नए क्रियम तो स्वयं नई कर व्यवस्था निर्मला सीतारमण ने प्रबन्ध बजट पेश करते हुए व्यवस्था की घोषणा की थी। व्यवस्था के तहत 12 लाख कर नहीं देना होगा जब रुपये थी। छूट सीमा में बढ़ाव अबतक की सबसे बड़ी प्रभावित होने से जुड़े प्रबन्ध कहा, लोग अब भी बचत के जरिए व्यवहार में बदल लेकिन लोग अब इतने कर सकते हैं कि उन्हें विकल्प बचत या कितना निवेश

पुरानी कर व्यवस्था एक-दो साल में नई दिल्ली (भाषा)। राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख स्पष्ट तक की छूट से पुरानी कर व्यवस्था के खुद ही एक-दो साल में समाप्त हो जाने की संभावना है। पांडेय ने यह भी कहा कि कर का दायरा बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई), अंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। वित्त एवं राजस्व सचिव पांडेय ने पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा, हम नई कर व्यवस्था लाए हैं। उसका मकसद ही यही है कि आप छूट के बारे में हर समय सोचने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करें। यह पूछे जाने पर कि क्या पुरानी कर व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, उन्होंने कहा, बजट में पुरानी कर व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें छूट है, कर की दर और स्लैब अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि एक-दो साल में पुरानी कर व्यवस्था अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इतनी बड़ी छूट दी है तो 2025-26 में प्रायः सभी करदाता नई व्यवस्था में आ जाएंगे।

पांडेय ने कहा, अगर आपको 12 लाख रुपए की अधिनियम में क्या रु

वर्य समाप्त हो जाएगीः राजस्व सचिव

तो आप कहां जाएंगे? सब ऐसे तो जल्द ही पुणी कर देंगे। वैसे भी नई कर व्यवस्था अपने पुणी को नहीं चुना है, मैं आ जाएंगे। वित्त मंत्री फरवरी को अपना आठवां गत आयकर सीमा में वृद्धि कर रखता था जो कोई नहीं कर सकता था क्योंकि उसका लाख स्पष्ट तक आयकर सीमा में वृद्धि है। दीर्घकालीन बचत विधान सभावल के जबाब में उन्होंने और निवेश करेंगे। कर नीति वाल का एक रुख रहा है... पक्का हो गए हैं कि वे निर्णय लेंगे जो खपत करनी है या कितनी रासन है। के प्रसारित नए आयकर होगा, उन्होंने कहा, नया

कानून छोटा व सरल होगा। उसे समझने में आसानी होगी। पुणे पड़ चुके प्रावधानों को हटाया गया है। चीजें को एक जगह लाया गया है। इससे कानूनी विवाद कम होगा। सीतासमन ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार आने वाले सप्ताह में संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो 1961 के आयकर कानून की जगह होगा। कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अन्य बातों के अलावा, कर आधार बढ़ाने के लिए एआई, ऑकड़ा विश्लेषण का भी उपयोग किया जा रहा है। राजस्व सचिव ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सामाजिक तौर पर राजस्व (आयकर) में 20 प्रतिशत के आसपास वृद्धि होती है। इस साल हमने 14 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कर छूट की वजह से राजस्व में एक लाख करोड़ स्पष्ट की कमी आने को ध्यान में खेते ही वृद्धि का यह लक्ष्य रखा गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या आर्थिक वृद्धि दर कम होने से राजस्व संग्रह पर असर होगा, पांडेय ने कहा, बाजार मूल्य पर वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत रखी गई है।

पुरानों कर व्यवस्था एक-दो साल में स्थिर समाप्त हो जाएगी: राजस्व सचिव

नड दिल्ला (भाषा)। राजस्व सचिव तुहन करत पांडेय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख स्पष्ट तक की छूट से पुणी कर व्यवस्था के खुद ही एक-दो साल में समाप्त हो जाने की संभावना है। पांडेय ने यह भी कहा कि कर का दायरा बढ़ाने के लिए वृत्रिम मेधा (एआई), आंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। वित एवं राजस्व सचिव पांडेय ने पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा, हम नई कर व्यवस्था लाए हैं। उसका मकसद ही यही है कि आप छूट के बारे में हर समय सोचने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करें। यह पूछे जाने पर कि क्या पुणी कर व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, उहोंने कहा, बजट में पुणी कर व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें छूट है, कर की दर और स्लैब अलग-अलग हैं। उहोंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि एक-दो साल में पुणी कर व्यवस्था अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इतनी बड़ी छूट दी है तो 2025-26 में प्रायः सभी करदाता नई व्यवस्था में आ जाएंगे।

पांडेय ने कहा, अगर आपको 12 लाख स्पष्ट की आय पर कर छूट चाहाये तोग नई व्यवस्था में व्यवस्था समाप्त हो जा डिफर्लेट है। यानी अगर तो स्वयं नई कर व्यवस्था निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष बजट पेश करते हुए व्यवस्था की घोषणा की थी। व्यवस्था के तहत 12 लाख स्पष्ट कर नहीं देना होगा जबकि स्पष्ट ही थी। छूट सीमा में अवक्त की सबसे बड़ी प्रभावित होने से जुड़े हैं। कहा, लोग अब भी बच्चे के जरिए व्यवहार में लेकिन लोग अब इतने कर सकते हैं कि उन्हें बचत या कितना निवेश

ता अप कहा जाएग ? सब लंगे तो जल्द ही पुरानी कर देंगे। वैसे भी नई कर व्यवस्था अपने पुरानी को नहीं छुना है, बल्कि में आ जाएंगे। वित्त मंत्री फरवरी को अपना आठवां वित्त वित्तानात आयकर सीमा में वृद्धि बढ़ाव करदाताओं को नई कर स्पष्ट तक की आय पर कोई पहले यह सीमा सात लाख अंचल लाख स्पष्ट की बढ़ोतारी वृद्धि है। दोधंकलीन बचत सवाल के जवाब में उन्होंने और निवेश करेंगे। कर नीति नाव का एक रख रहा है... एक हो गए हैं कि वे निर्णय भी खपत करनी है या कितनी जल्दी है।

के प्रस्तावित नए आयकर वित्तानात होगा, उन्होंने कहा, नया कनून छाया व सरल होगा। उस समझन म आसान होगी। पुराने पड़ चुके प्रवधानों को हटाया गया है चीजों को एक जगह लाया गया है। इससे कनून विवाद कम होगा। सीतारमण ने शनिवार को वित्त वित्त 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था वित्त सरकार आने वाले सप्ताह में संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो 1961 के आयकर कानून के जगह लेगा। कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने कहा, अन्य बातों के अलावा, कर आधार बढ़ाने के लिए एआई, अंकड़ा विश्लेषण व भी उपयोग किया जा रहा है। राजस्व सचिव ने एवं अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सामान्य तौर पर राजस्व (आयकर) में 20 प्रतिशत के आसपास वृद्धि होती है। इस साल हमने 14 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कर छूट की वजह से राजस्व में एक लाख करोड़ स्पष्ट की कमी आने को ध्यान में खेले ही वृद्धि का यह लक्ष्य रखा गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या आर्थिक वृद्धि दर कम होने से राजस्व संग्रह पर अस होगा, पांडेय ने कहा, बाजा मूल्य पर वृद्धि दर 10. प्रतिशत रखी गई है।

दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आईएएस बनने में कांग्रेस ने योड़ा पैदा किया: अनुप्रिया

शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए लिया, जो एमसीसी उल्लंघन का पप्लिम ने कहा कि उन्होंने मनीष प्रिपोर्टिंग कर रखे थे और उन्होंने

युलिस न कहा कि उन्हें नाम प्रबिधूड़ी और रवि दयामा को आदर्श आचार संहिता (एम्सीसी) का उल्लंघन करते पाया। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाद में, दूसरी कॉल पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने लगभग 10 वाहनों के साथ आप कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ देखी। डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) रवि कुमार सिंह ने बताया कि बार-बार हटने का अनुरोध करने पर भी आप सदस्यों ने इनकार कर दिया और निषेधाज्ञा तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। डीसीपी ने बताया कि पफ्लाइंग स्कायड टीम की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने घटनास्थल की बीडियोग्राफी शुरू की तो कुछ आप कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक हेड कांस्ट्रेल के साथ मारपीट और दुर्घटनाक हत्या किया, उसका फोन छीन लिया और उसे घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमले के संबंध में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है। यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिरिक्त का नाम विशेष रूप से एफआईआर में है, डीसीपी सिंह ने पुष्टि की कि घटनास्थल पर मौजूद और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता ने आरोप लगाया कि कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुले आम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रक्रम पर एक पोस्ट में कहा चन्नानाथ रापाणी का रहे थे।' उन्होंने आप लगाया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों द्वारा खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। एक्स पर बीडियो शेयर करते हुए आतिशी ने कहा, 'बीडियो बना से लड़के को पुलिस ने पीटा और उन्हें गई। आप इस बीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस उसे लात मार रही है। बीडियो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा खिलाफ कार्रवाई की गई। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं है।' उन्होंने दावा किया कि विलाप कालकाजी से उनके भाजपा प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी और उनके परिवार ने सदस्य खुले आम 'गुण्डागर्दी' कर रखे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्होंने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। आप के राष्ट्रीय संयोजन अर्विद के जरीवाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने वह दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का 'आधिकारिक रुख' है, जो आप के खिलाफ भाजपा की 'गुण्डागर्दी' का समर्थन करते हैं और शाराब और पैसे वितरित करते समय उन्हें संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा, 'यदि कोई उसके रोकता है तो उसके खिलाफ काम बाधा डालने का मामला दर्ज किया जाएगा।' पुलिस के अनुसार, जब उससे जाने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद, वरिष्ठ आप नेता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अवज्ञा का मामला दर्ज किया गया जबाबद में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि विलाप की मुख्यमंत्री अपनी 'आसन्न हार' की घबरा रही है और उन्होंने सुशाव दिल्ली के उद्देश्य पर्यावरण संविधानिक पर विवाद किया।

वास्ते न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि भाजपा की ज्यादा दिलचस्पी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति में है। उन्होंने दावा किया, गुजरात में 14 प्रतिशत आदिवासी हैं। यूसीसी आदिवासी समाज की संस्कृति, रीति-रिवाज, धार्मिक परंपराओं और विवाह संस्कार को प्रभावित करेगा। इसी तरह, गुजरात का जैन समुदाय और देवीपूजक भी इससे प्रभावित होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय संविधान ने भी कुछ समुदायों को अपने रीति-रिवाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने दावा किया, यूसीसी का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, न कि राज्य के। चूंकि पूरे गुजरात में भाजपा में अंदरूनी लड़ाई जारी है और यहां की सरकार हर तरह से नाकाम रही है, इसलिए यह घोषणा शहरी निकाय चुनावों से पहले लोगों

दानिश सिंहीकी ने कहा कि यूसीसी का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और यह भी कहा कि उन्हें सरकार द्वारा गठित समिति से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के अल्प-अलग विचारों पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों को प्रस्तावित कानून से बाहर रखा जाता है, तो यह यूसीसी नहीं कहलाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया, हम पैनल के समझ अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा बहुविवाह को लेकर मुसलमानों पर तो निशान साधती है तो उसे यह पता होना चाहिए कि अन्य समुदायों में भी यह प्रथा प्रचलित है। जब एक समुदाय को (बहुविवाह को) अनुमति दी जाती है और अन्य को नहीं, तो यह यूसीसी नहीं कहलाएगा। समिति की सदस्य गीता औफ ने कहा कि उनका दृढ़ापूर्वक मानना है कि एक समान कानून से कई लाभ होंगे। उन्होंने कहा, पिछले 30 वर्षों में मैंने देखा कि

का ध्यान भटकाने का काशशश ह।

आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख इसुदान गढ़ीने कहा कि जब भी चुनाव होता है, भाजपा यूसीसी का मुहा उठाती है। उन्होंने दावा किया, आज भी, मालधारी समुदाय में घेरेलू विवाद के 80 प्रतिशत मामले उसके नेताओं द्वारा सुलझाए जाते हैं। अदिवासी समाज में बहुविवाह प्रथा है और अगर यूसीसी लागू होता है तो ए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए, हमारा मानना है कि यूसीसी ईसाइयों, सिखों, मुसलमानों के लिए अडचन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में यूसीसी लागू होता है, तो भाजपा एक भी अदिवासी सीट नहीं जीत पायगी। गढ़ीने के कदमों में भाजपा को

एकस तरह न्याय का लड़ाई के लिए महिलाओं और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूसीसी से इन कठिनाइयों को दूर करेगा। ठाकरे ने कहा कि पर्सनल लॉ के कारण महिलाओं पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उच्चतम न्यायालय ने शह बागे मामले में निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों में विरोधाभासों को दूर किया जाना चाहिए और एक समान कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यहां तक कि संविधान सभा ने भी मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए हैं जिनमें इसके लिए प्रावधान हैं। हम जानते हैं कि उत्तराखण्ड ने समान नागरिक संहिता लागू की है।

जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रम्प ने कहा था कि भारत अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के मामले में 'वही करेगा जो सही होगा।' उन्होंने कहा, हम उन्हें वापस ले लेंगे, बशर्ते कि हमारे साथ दस्तावेज साझा लाखों-करोड़ों अवैध विदेशियों को उनके स्थानों पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जहां से वे आए थे। ट्रम्प प्रशासन ने सीमा शुल्क और सीमा गश्ती एजेंसी के तहत सीबीपी वन मोबाइल एप्लिकेशन को भी बंद कर दिया है, जो प्रवासियों को सीमा

करें, ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे वास्तव में भारतीय हैं। साथ ही, जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या के बारे में बात करना अभी 'जल्दबाजी' होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अमेरिका से किसे भारत भेजा जा सकता है, तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। जयशंकर ने कहा था, हर देश के साथ, और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है, हमने हमेशा यह कहा है कि यदि हमारा कोई नागरिक वहाँ अवैध रूप से है, और यदि हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। प्यूरिसच्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, भारत से लगभग 725,000 अवैध अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं, जिससे यह मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद अनधिकृत अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। ट्रम्प ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, जब मैं दोबारा निर्वाचित होऊंगा तो हम अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अधियान शुरू करेंगे। बड़े पैमाने पर यह निर्वासन सीमा प्रवर्तन पर अमेरिकी सरकार के दृढ़ रुख को रेखांकित करता है और इससे देश में अवैध रूप से रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। ट्रम्प की अप्रवासी-विरोधी बयानबाजी 2024 में अमेरिकी चुनावों के लिए उनके अधियान के लिए महत्वपूर्ण थी। जब उन्होंने जनवरी में पदभार संभाला, तो उन्होंने दोहराया कि सभी अवैध अप्रवासियों को वापस भेज दिया जाएगा। ट्रम्प ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा, सभी अवैध प्रवेश को तुरंत रोक दिया जाएगा, और हम

